Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 16-03-2005

Participants : Chandel Shri Suresh

>

Title: Need to lift the ban on recruitment to Group 'C' posts in the Postal Department.

श्री सुरेश चन्देल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के पदों को भरने के लिए लगभग प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका सबसे प्रतिकूल प्रभाव डाक विभाग के कर्मियों पर पड़ रहा है। वहां जो पद रिक्त हो रहे हैं, उनमें से 67 प्रतिशत पद खत्म हो रहे हैं और बाकी 33 प्रतिशत पदों को भरने के लिए निर्णय लिया गया है कि ये पद स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन दो साल तक उस कमेटी की मीटिंग न होने के कारण वे 33 प्रतिशत पद नहीं भरे जा रहे हैं, जिसके कारण रिक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में इस कारण बड़ी कठिनाई आ रही है। लोगों को अपने टेलीफोन बिल जमा कराने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस पर विभाग वाले कहते हैं कि नियुक्तियों पर प्रतिबंध के कारण हम स्टाफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती है कि कम से कम इस नीति को बदला जाए। आज तक डाक विभाग में 38,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। 'ए' और 'बी' केटेगरी पर, अधिकारियों के पदों पर, कोई प्रतिबंध नहीं है, उनके पद भरे जा रहे हैं। लेकिन जो काम करने वाले नीचे के कर्मी हैं, उनके पद समाप्त हो रहे हैं।

बेसिक कठिनाई यह है कि काम न करने वाले लोगों के कारण कठिनाई बढ़ रही है। यदि यह नीति लागू होनी है तो अफसरों के पदों को भी कम किया जाए। इस दृटि से सरकार इस पर पुनः विचार करे और जो ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं उनके पदों को भरने की ओर सरकार ध्यान दे ताकि दूरदराज के लोगों को जो कठिनाई हो रही है वह दूर हो।